



न्यूज़ ब्रीफ

घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमत हर शहर में अलग-अलग होती है



नई दिल्ली। भारत में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसकी कीमतों में घट-बढ़ का असर सीधे रसोई के बजट पर पड़ता है, जहां आम उपभोक्ताओं की नजर घरेलू सिलेंडर के रेट पर रहती है। वहीं, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और कैटरिंग सर्विस चलाने वाले कमर्शियल एलपीजी कीमतों पर बारीकी से नजर रखते हैं क्योंकि यह उनके रोज के खर्च का एक नियमित हिस्सा है। पूरे भारत में एलपीजी की कीमतें एक जैसी नहीं होती हैं। घरेलू या कमर्शियल सिलेंडर की कीमत एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग हो सकती है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपए है। एलपीजी सिलेंडर की रिटेल कीमतों पर करंसी में उतार-चढ़ाव, ट्रांसपोर्ट का खर्च और लागू टैक्स जैसे कई कारकों का असर पड़ता है। राज्य सरकारें एलपीजी सिलेंडर पर अपने हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स और स्थानीय कर लगाती हैं, चूंकि हर राज्य में टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं इसलिए राज्यों की सीमाओं के पार होते ही सिलेंडर की कीमतें भी बदल जाती हैं। गैस सिलेंडर रिफाइनरी या एलपीजी बटलिंग प्लांट से आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर तक टुकों या ट्रेनों के जरिए पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में प्लांट से जिस शहर की दूरी जितनी ज्यादा होगी, भाड़ा उतना ही ज्यादा लगेगा।

भारत में सितंबर में आटो रिटेल बिक्री 31.8 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 25.37 लाख



मुंबई। त्यौहारी मांग और बीते साल के कम आधार के चलते सितंबर में भारत की आटोमोबाइल रिटेल बिक्री में जोरदार उछाल दर्ज हुआ है। फेब्रेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 25.36,920 इकाई पहुंच गई। अगस्त की तुलना में भी बिक्री में 4.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। फाडा ने कहा कि सितंबर उद्योग के लिए अब तक का सबसे बेहतर महीना रहा। हालांकि, सालाना वृद्धि को सितंबर 2025 के कम आधार के संदर्भ में देखना चाहिए। बीते साल जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले ग्राहकों ने खरीदारी टाल दी थी, जिससे बिक्री प्रभावित हुई थी। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कुल आटो रिटेल बिक्री 1,55,12,319 इकाई रही, जो पिछले साल की समान अवधि से 20.77 प्रतिशत अधिक है। श्रेणीवार आंकड़ों में दोपहिया वाहनों की बिक्री 33.08 प्रतिशत बढ़कर 17,90,188 इकाई रही। यानी वाहनों की बिक्री 32.10 प्रतिशत बढ़कर 4,27,213 इकाई पहुंच गई। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.62 प्रतिशत बढ़कर 1,03,557 इकाई रही और पहली बार यह आंकड़ा एक लाख के पार गया। तिपहिया वाहनों की बिक्री 22.25 प्रतिशत बढ़कर 1,32,570 इकाई और ट्रैक्टर बिक्री 13.75 प्रतिशत बढ़कर 76,906 इकाई रही। सितंबर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी रिकार्ड स्तर पर पहुंची। सभी श्रेणियों को मिलाकर करीब 3.34 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिससे कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत रही।

एलजी ने घोषित किए ‘सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट’ दिवाली ऑफर्स

नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने दिवाली के अवसर पर ‘सेलिब्रेशन ऑफ ट्रस्ट’ अभियान के तहत होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष ऑफर्स की घोषणा की है। चुनिंदा मॉडल्स पर ग्राहकों को 26 प्रतिशत तक का कैशबैक, 30,000 रुपये तक की बचत, 888 रुपये से शुरू होने वाली फिक्स्ड ईएमआई और जीरो डाउन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। चुनिंदा एलजी टीवी पर तीन साल की वारंटी, साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर पर 14,190 रुपये तक का मिनी रेफ्रिजरेटर और चुनिंदा वॉटर प्यूरीफायर पर 4,200 रुपये की फ्री मेंटेंसेंस सुविधा भी दी जाएगी। कप्रेसर पर 10 साल की वारंटी और एलजी बेस्टकेयर एएमसी पर 30 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। यह प्रमोशन 15 नवंबर तक चलेगा।

नईदुनिया

महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट का सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आ रहा है। भाव में आए बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 970 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,060 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में आई तेजी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,50,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,37,710 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,37,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच

बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,50,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,50,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,760 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,37,710 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,710 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,50,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,37,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,50,380 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की

कीमत 1,50,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,37,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,50,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,37,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियां बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने वाणिज्यिक सहयोग का किया विस्तार

नई दिल्ली। एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत तथा सिंगापुर के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को उड़ानों के अधिक विकल्प देने के मकसद से अपने वाणिज्यिक सहयोग के विस्तार की घोषणा की है। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया ने बुधवार को ‘एक्स’ पोस्ट में कहा कि भारत-सिंगापुर के बीच सफर करने वाले अपने ग्राहकों को ज्यादा सुविधा और लचीलापन देने के लिए हम सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा, “इसमें सिंगापुर और भारत के आठ शहरों, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता और मुंबई- के बीच हर हफ्ते 126 उड़ानें



शामिल हैं।” फिलहाल, सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) के जरिये बुक की जाने वाली एयर इंडिया संचालित पात्र कोड शेयर उड़ान के साथ एसआईए द्वारा संचालित उड़ान को शामिल करना जरूरी है। इसके उलट एयर इंडिया के लिए भी यही नियम है। यह शर्त 15 अक्टूबर से हटा दी जाएगी।

दोनों में से किसी भी एयरलाइन की योग्य उड़ानों को दूसरी एयरलाइन के बुकिंग चैनलों के जरिए बुक करना आसान हो जाएगा, जिससे यात्रा की योजना बनाना और भी आसान तथा सुविधाजनक हो जाएगा। एयर इंडिया ने कहा कि आगे की बात करें तो महाराजा क्लब और क्रिसफ़्लायर के सदस्यों को 2027 की दूसरी तिमाही से बेहतर आपसी फ़ायदे मिलेंगे, जिससे अक्सर यात्रा करने वालों के लिए इसकी अहमियत और बढ़ेगी। इससे बेहतर कनेक्टिविटी, ज्यादा विकल्प और ज्यादा फायदेमंद यात्राएं। उल्लेखनीय है कि विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया की 25.1 फीसदी हिस्सेदारी है।

भारत में स्टारलिक की एंट्री लगभग तय अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली : इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिक भारत में शुरू होने के करीब है। कंपनी ने सेवा शुरू करने के लिए जरूरी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब स्टारलिक को अंतिम नियामकीय मंजूरी का इंतजार है। देशभर में स्टारलिक ने 20 गेटवे साइट तैयार की हैं। ये जमीन पर बने स्टेशन हैं, जो अंतरिक्ष में मौजूद स्टारलिक के सैटेलाइट को जमीन के मुख्य इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ते हैं। इन स्थानों पर सैकड़ों एंटीना लगाए गए हैं, ताकि इंटरनेट सिग्नल का निर्बाध रूप से आदान-प्रदान हो सके। स्टारलिक भारत में नेटवर्क का विस्तार करने के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ शुरुआती सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने महाराष्ट्र, गुजरात और मेघालय सरकारों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी



हस्ताक्षर किए हैं। स्टारलिक स्पेसएक्स की परियोजना है, जो सैटेलाइट के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। इसके सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होते हैं, जिससे कम विलंबता वाला

इंटरनेट उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। यह सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकती है, जहां पारंपरिक इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सीमित है। स्टारलिक वर्ष 2022 से भारत में सेवा शुरू करने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण लाइसेंस प्रक्रिया में देरी हुई। भारत सरकार ने डेटा सुरक्षा और कॉल इंटरसेप्शन जैसी शर्तें रखी थीं, जिन्हें कंपनी ने स्वीकार किया है। सेवा शुरू होने के बाद दूर-दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कारोबार जैसी सेवाओं को लाभ मिल सकता है। सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिक किंग में डिश, वाई-फाई राउटर, बिजली की केबल और मॉडिंग ट्राइपॉड शामिल होते हैं। बेहतर सिग्नल के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखना आवश्यक होता है।

भारत के सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार बढ़ी, सितंबर में पीएमआई तीन महीने के शीर्ष स्तर 55.2 पर



नई दिल्ली। भारत के सर्विसेज सेक्टर की गतिविधियों में सितंबर में तेजी दर्ज हुई। मजबूत घरेलू मांग और नए आईस में बढ़ोतरी के चलते सेवा क्षेत्र का पीएमआई अगस्त के 54.1 से बढ़कर सितंबर में 55.2 पर पहुंच गया। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार किए गए पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक, यह जुन के बाद सर्विसेज पीएमआई का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर में नए बिजनेस में वृद्धि की रफ्तार भी बीते तीन महीनों में सबसे तेज रही। कंपनियों ने डिजिटल समाधान, खाद्य एवं पेय पदार्थ, बीमा, ऋण, साफ्टवेयर, परिवहन और पर्यटन एवं यात्रा सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की। एएसबीसी इंडिया के मुताबिक, वित्त, बीमा और उपभोक्ता सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में बिक्री में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। एएसबीसी इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि पीएमआई सर्वेक्षण से घरेलू मांग में मजबूती के कारण सेवा क्षेत्र में लगातार सुधार का संकेत मिलता है। उनके अनुसार, निर्यात कारोबार में भी वृद्धि जारी रही, हालांकि इसकी रफ्तार कुछ धीमी हुई। सितंबर में इनपुट लागत का दबाव कम होने से सेवा प्रदाताओं पर कीमतें बढ़ाने का दबाव भी घटा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सेवाओं की मांग में भी सुधार दर्ज किया गया। कंपनियों ने जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका से बेहतर कारोबार की जानकारी दी। हालांकि, नए निर्यात आईस की वृद्धि दर सितंबर में धीमी पड़ी। मजबूत आर्डर बुक और पाइपलाइन में मौजूद परियोजनाओं के चलते सेवा कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई। रोजगार में वृद्धि अच्छी रही, हालांकि अगस्त के मुकाबले इसकी रफ्तार थोड़ी कम रही।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान बढ़त बना कर बंद होने में सफल रहे। वहीं एशियाई बाजार में आमतौर पर दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमी आने और कच्चे तेल की कीमत में स्थिरता का संकेत मिलने के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी का माहौल बना रहा। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 253.14 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की मजबूती के साथ 51,521.04 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.58 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,818.93 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 122.48 अंक यानी 0.45 प्रतिशत उछल कर 27,599.79



अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 51,486.70 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार उसाह का माहौल बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,541.69 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसई इंडेक्स ने 0.39 प्रतिशत की उछाल के साथ 7,865.07 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएक्स इंडेक्स 194.98 अंक यानी 0.77 प्रतिशत की छलांग लगा कर 25,449.19 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। एशियाई बाजार में दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजारों में से सात के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि दो सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,842.19 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह सेंट

कंपोजिट इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,586.08 अंक के स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, निफ्ट निफ्टी 134.50 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,639.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.63 प्रतिशत फिसल कर 6,153.99 अंक के स्तर पर आ गया है। कोसपी इंडेक्स में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 0.99 प्रतिशत टूट कर 6,872.87 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। निक्केई इंडेक्स में भी लगातार दबाव बना हुआ है। फिलहाल यह सूचकांक 527.98 अंक यानी 0.75 प्रतिशत लुढ़क कर 70,156 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा हैंग सेंग इंडेक्स 160.56 अंक यानी 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,120 अंक के स्तर पर, स्ट्रैस टाइम्स इंडेक्स 0.15 प्रतिशत टूट कर 5,620.18 अंक के स्तर पर और ताईवान वेटेड इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 49,809.52 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

महंगाई को काबू करने साढ़े तीन साल बाद बढ़ी रेपो रेट



नई दिल्ली रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने लगातार बढ़ी रही खाद्यान्नों पर महंगाई को काबू करने के लिए आखिरकार साढ़े तीन साल बाद (43 महीने) रेपो रेट बढ़ा ही दिया। महंगाई और ग्लोबल मार्केट के तमाम दबाव के बावजूद अभी तक आरबीआई ने इसे काबू में रखा था, लेकिन आखिरकार इसमें 0.25 फीसदी रेट बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.50 फीसदी पहुंच गया है, जो अभी तक 5.25 फीसदी रहा था। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, आटो लोन समेत अन्य सभी तरह के खुदरा लोन की ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर मकान खरीदारों पर पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने पिछले तीन दिनों से चल रही मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद इसके फैसलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि महंगाई के दबाव में आखिरकार रेपो रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। गवर्नर ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया और अब प्रभावी रेपो रेट बढ़कर 5.50 फीसदी पहुंच गया है। इसका सीधा असर होम लोन, आटो लोन समेत अन्य सभी तरह के खुदरा कर्ज पर पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादातर बैंकों की ब्याज दरें रेपो रेट से ही जुड़ी होती हैं। रेपो रेट में यह बढ़ोतरी फरवरी, 2023 के बाद पहली बार की गई है। गवर्नर ने बताया कि स्टैंडिंग

होम लोन समेत सभी खुदरा लोन की बढ़ती ईएमआई रेपो रेट में यह बढ़ोतरी फरवरी, 2023 के बाद पहली बार की गई

डिफाजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ की दरों को 5.25 फीसदी पर बककर रखा है, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 5.75 फीसदी पर बनाए रखा है। आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ाने के साथ ही अपने रुख को भी न्यूट्रल से बदलकर सख्त कर दिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने अगर महंगाई की ब्याज दरें नहीं सुधरों तो रेपो रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ग्लोबल मार्केट में जारी उठापटक और घरेलू बाजार में ईंधन महंगा होने के बाद खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का दबाव बढ़ा दिया है। इसी दबाव के कारण साढ़े तीन साल बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ाना पड़ा है। चीनी 5.50 फीसदी बढ़ चुकी है। इसका सीधा असर होम लोन, आटो लोन समेत अन्य सभी तरह के खुदरा कर्ज पर पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादातर बैंकों की ब्याज दरें रेपो रेट से ही जुड़ी होती हैं। रेपो रेट में यह बढ़ोतरी फरवरी, 2023 के बाद पहली बार की गई है। गवर्नर ने बताया कि स्टैंडिंग

जीएसटी काउंसिल की बैठक, आनलाइन फूड डिलीवरी लागत को लेकर होगा फैसला

आनलाइन मंगाने वाला खाना होगा सस्ता, डिलीवरी फीस 5 फीसदी कर सकती है सरकार

नई दिल्ली 8 अक्टूबर यानी गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें आनलाइन फूड डिलीवरी की लागत से जुड़ा फैसला हो सकता है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ सकता है। डिलीवरी चार्ज पर लगने वाला जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव विचारधीन है। हालांकि, अंतिम फैसला बैठक में ही होगा।

मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक आनलाइन प्लेटफार्म से खाना ऑर्डर करने पर खाने की कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन डिलीवरी फीस को अलग सेवा मानते हुए उस पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाता है। अब जीएसटी काउंसिल इस अंतर को खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो स्विगी और ज़ोमेटो जैसे प्लेटफार्म पर लगने वाली



डिलीवरी फीस पर भी 5 फीसदी जीएसटी लागू हो सकता है। इससे बिलिंग व्यवस्था आसान होने के साथ ग्राहकों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में होटल, रेस्टोरेंट और फिटेनेस सेंटर जैसे कारोबारों के लिए आईटीसी से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में है। 5 फीसदी जीएसटी देने वाले इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ इनपुट खर्चों पर टैक्स क्रेडिट देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे कारोबारियों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को लेकर भी अहम फैसला कर सकती है। सात और दुर्लभ बीमारियों को जीएसटी छूट वाली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे महंगी

और जीवनरक्षक दवाओं पर मरीजों का आर्थिक बोझ कम हो सकता है। डिफेंस सेक्टर में मिसाइल के पुर्जों, स्पेयर पार्ट्स और विशेष टेस्टिंग उपकरणों को आजीजीएसटी छूट देने पर विचार हो सकता है। वहीं, कृषि बीजों की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव भी सामने है। इसके अलावा विदेशी शिपिंग कंपनियों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं और सिमिनस प्रोविडेंट फंड ओरगनाइजेशन की सेवाओं को भी टैक्स राहत देने पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक गुव्वार को होगी, फिलहाल ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इन पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।